12.58 hrs

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF
PROFIT

SECOND REPORT

SHRI D BASUMATARI (Kokrajhar) :
I beg to present the Second Report of the
Joint Committee on Office of Profit on the
Draft Parliament (Prevention of Disqualifica-
tion) Amendment Bill, 1971

DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS)
BILL*

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI
F. H. MOSHIN) On behalf of Shri Ram
Niwas Mirzha, I beg to move for leave to
introduce a Bill to provide for the speedy
trial of certain offences in certain areas and
for matters connected therewith

MR. SPEAKER . The question is

"That leave be granted to introduce a Bill
to provide for the speedy trial of certain
offences in certain areas and for matters
connected therewith"

The motion was adopted

SHRI F. H. MOSHIN I introduce the
Bill.

CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL*

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI
F. H. MOSHIN) On behalf of Shri Ram
Niwas Mirzha, I beg to move for leave to
introduce a Bill further to amend the Indian
Penal Code, the Code of Criminal Procedure,
1898 and the Unlawful Activities (Prevention)
Act, 1967.

MR. SPEAKER . Motion moved

"That leave be granted to introduce a Bill
further to amend the Indian Penal Code,
the Code of Criminal Procedure, 1898 and
the Unlawful Activities (Prevention) Act,
1967."

श्री अटक बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) .
अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के पेश किये जाने
का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैंने
आप की सुचना दी है, मैं इस समय विधेयक के
ब्योरे में नहीं जा रहा हूँ, इसके गुण और बोंबों
की चर्चा नहीं कर रहा हूँ यद्यपि मैं जानता
हूँ कि यह विधेयक बड़ा शरारतपूर्ण है और
यह साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिये
नहीं लाया जा रहा है, यह मुस्लिम संगठनों के
विरोध नहीं है। इसके अन्तर्गत केवल हिन्दू संगठनों
के खिलाफ कार्यवाही की जायगी, इसके विरोध
हम सदन में भी लड़ेंगे और बाहर भी लड़ेंगे।

लेकिन यहाँ मैं दूसरी बात कह रहा हूँ।
एक तरीका बन गया है—आप द्वारा दिये गये
निर्देशों और सदन द्वारा पारित नियमों के खिलाफ
भंत्रियों को विधेयक पेश करने की इजाजत देने
का/आप डायरेक्शन्स के नियम 19(ए) को देखें—

"A Minister desiring to move for leave to
introduce a Bill shall give notice in writing
of his intention to do so"

आगे कहा गया है—

"at least seven days"

अर्थात् इसके लिये सात दिन का नोटिस
होना चाहिये।

अब इस विधेयक को मैंने देखा—इस पर
श्री आर० एन० मिर्झा जी के दस्तखत हैं और
दस्तखत के साथ 27 मई की तारीख दी गई है।
स्पष्ट है कि सात दिन का नोटिस पूरा नहीं किया
गया।

अध्यक्ष महोदय . इसे मैंने एलाउ किया है।

श्री अटक बिहारी बाजपेयी : अगर आप
एलाउ करते जा रहे हैं तो फिर ये नियम बनाये
क्यों गये हैं। यदि आप अपने अधिकारों का इस
तरह से उपयोग करेंगे तो नियमों की यह पुस्तिका
रही की टोकरी में फेंकने लायक हो जायगी।
अभी उस दिन आने में शिक्षा मंत्री जी को विधेयक

कमि की छूट दे दी, उस दिन नियमों को ताक पर रख दिया गया। कल आप ने बिल मंत्री जी की छूट दे दी—ज्वाइंट, सिलेक्ट कमेटी बनाने के लिये, जिस की इजाजत न सविधान देना है, न बियन की किताब देती है। यह बिल क्या पहले नहीं लाया जा सकता था। यह बिल पास करने के लिये नहीं है, खाली पेश किया जा रहा है, क्या इसको अगले सेशन में पेश नहीं किया जा सकता था। आखिर नियम किस लिये बनाये गये हैं—एक—आध मामले में कोई असाधारण परिस्थिति हो तो आप नियम देव करते, लेकिन यहाँ तो एक अपवाद नियम बन गया है। मुझे सबमुच बड़ा रोष है और मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह से इजाजत दे रहे हैं उससे न नियमों की प्रतिष्ठा बढ रही है और न लोक सभा की गरिमा बढ रही है। आप नियमों का पालन नहीं करते तो हम लोगो से भी नियमों का पालन करने की आशा न की जाय।

13 hrs.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे काफी महमत हूँ। इससे इजाजत दी गई है। जब सेशन खत्म होने को जाता है तो आम तौर पर यही चलता है, गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि यह बिल रह गया, वह बिल रह गया, इस बिल को इसी सेशन में पास करना चाहते हैं तो जो रीजन्स गवर्नमेंट देती है उनसे अगर मैं कन्वन्स हो जाऊँ तब इजाजत देता हूँ। स्पीकर को आपने इसीलिए यह अख्तियार दिए हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो यह अख्तियार आपसे लीजिए। लेकिन अगर यह अख्तियार आप देते हैं तब फिर यह गलत बात है कि आप हर दफा खड़े होकर कहें कि क्यों इजाजत दे दी। गवर्नमेंट जो रीजन्स देती है अगर वह कन्वन्स होती है तो मैं इजाजत देता हूँ।

... (अध्वधान) ...

तब तो वह गवर्नमेंट इजाजत मागे तब दे दी जाये यही रखा जाये। ... (अध्वधान) ...

श्री जगन्नाथ राय बोसी (शाजापुर) : इसी सत्र में इस विधेयक को पेश करने की क्या आवश्यकता थी? अगले सत्र में भी यह जा सकता था। ... (अध्वधान) ...

अध्यक्ष महोदय : कुछ रीजन्स बताये होंगे सभी तो मैंने इजाजत दी होगी।

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : एक एतराज तो उस तरफ से यह किया गया कि इस सत्र में यह पास नहीं हो रहा है अगर यह बिल इसी सेशन में पास कर दिया जाये तो हमें बड़ी खुशी होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पास करने का समय कहा है? हम कहते हैं कि बिना चर्चा के ही पास कर दीजिए। यदि अखिबेशन समाप्त हो जायें तो आइनेन्स निकाल दीजिए और जो इसके खिलाफ बोलते हैं उनको फाँसी पर चढ़ा दीजिए। ... (अध्वधान) ...

श्री फूलचन्द्र वर्मा (उज्जैन) : बहुमत के आधार पर यहाँ पर जंगल के कानून बन्दे जा रहे हैं। (अध्वधान) ...

अध्यक्ष महोदय : मैंने अच्छी तरह से देखकर इसको इजाजत दी है। यह नहीं कि यू ही दे दी है। स्पीकर का काम सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर बैठा रहे। कई दफा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आता है तो उससे गवर्नमेंट की भी कुछ झूटी होती है और आरक्षी अपोजीशन की भी कुछ झूटी होती है। अब वह दिन गुजर गए जब 9 स्पीकरों का गला काट दिया गया था। कभी किंग का कहना नहीं माना तो स्पीकर का गला काट दिया गया तो वह बातें अब चली गईं। अब रूस की बात है। रूस प्रोवाइडेड हीं और उनके मुताबिक मुझे इस्तीफा दिया गया है जिसको मुझे इस्तेमाल करना है। वैसे आपकी ब्यूज का हम आगे खयाल रखेंगे। ... (अध्वधान) ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा कि इस विधेयक को इसी समय लाना क्यों जरूरी था।

अध्यक्ष महोदय : फाइल आयुची तो बता दीस। आम तौर पर यही होता है कि स्पीकर

[अध्यक्ष महोदय]

जवाब नहीं देता है। ... (अध्यक्ष) ... अगर स्पीकर को एयारिटी है, डिस्क्रिशन है तो वह चलेगी वरना आप उसको वापिस ले लीजिए।
• (अध्यक्ष) • अगर आप मुझे भी हुक्म करें तो आपको फाइल दिव्या दू कि क्या रीजन्स हैं। कल आप एतराज करते थे कि उस मेम्बर ने फाइल क्यों लो, मैंने मिश्रा जी से बात की थी ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक बात मुझे और कहनी है। यह चीज सर्कुलेट की गई है, यह क्या है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बिल का कारिजेन्डम सर्कुलेट किया जा रहा है, क्या इसकी भी आपने इजाजत दी है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप हमारे साथ जबर्दस्ती कर रहे हैं। (अध्यक्ष)

अध्यक्ष महोदय आपको तो एक पार्टी लीड करनी है, आपमें इतनी तेजी आ जाये तो कैसे रोका जायेगा। ... (अध्यक्ष)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी यह यहाँ पर बाटा जा रहा है। • (अध्यक्ष) • यदि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बिल में कोई अमेन्डमेंट करना है तो वह सदन में आना चाहिए, इस तरह से नहीं आ सकता है।

अध्यक्ष महोदय इस समय मेरे सामने आइटम नं० 2, इंडियन पीनल कोड है और इस पर अभी वोटिंग नहीं हुई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे हाथ में यह आ गया तो मैंने कहा एक यह नयी मुसीबत आ गई। • (अध्यक्ष) •

अध्यक्ष महोदय : क्या अपोजीशन का यही काम है बात पर खड़े होना ? मैं जानता हूँ

अपोजीशन छोटा है, मेरा फर्क है, मैंने आपको एकोमोडेट करके और मैंने बड़े मामलों में आपको एकोमोडेट किया है, कभी डिस्क्रिशन क्लेम से एकोमोडेट किया है। अगर उसको जोबर-एग्जाजरेटेड समझें तो वह बात कल होगी। ... (अध्यक्ष) • •

श्री इयान मन्वान निख (वेगुसराय) : केयर को भी ममता होनी चाहिए और हमको भी। काम तौर पर जो भी विधेयक बायें उनको ऐसे ही न मान लें। ... (अध्यक्ष) • •

MR SPEAKER • The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967."

The motion was adopted

SHRI F H MOHSIN I introduce the Bill.

13.08 hrs.

HIRE PURCHASE BILL—Contd

MR. SPEAKER : We will now proceed with the further consideration of the Hire Purchase Bill Shri Somnath Chatterjee.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan) Mr Speaker, Sir •

So far as this Bill is concerned, I consider it as a welcome measure because it has become necessary to control the abuse of the hire purchase system on the part of financiers and various financial institutions and to save the hirers who generally hail from the weaker sections of the society. As I indicated yesterday, one of the greatest evils which has crept into this system is that the financiers were procuring the signatures from the hirers on forms in which blanks were there and they were being utilised by the financiers for filling in the blanks suitably. They have been taking signatures on bank promissory notes, blank hundis, etc., apart from taking penal interest.